

आरबीआई की ओर से प्रतिभागी:

श्री शक्तिकांत दास - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री महेश कुमार जैन - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

डॉ. माइकल डी. पात्रा - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री एम. राजेश्वर राव - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री टी. रबी शंकर - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

संचालक: श्री योगेश दयाल - मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

योगेश दयाल:

नमस्कार और इस नीति की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ गवर्नर श्री शक्तिकांत दास, और उप गवर्नर श्री एम.के. जैन, डॉ. माइकल डी. पात्रा, श्री एम. राजेश्वर राव, और श्री टी. रबी शंकर उपस्थित हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें; सर, मैं आपसे कुछ प्रारंभिक संबोधन करने का अनुरोध करूँगा, और उसके बाद हम प्रश्न-उत्तर सत्र शुरू करेंगे।

शक्तिकांत दास:

यह कोई औपचारिक संबोधन नहीं है, बल्कि केवल कुछ प्रारंभिक टिप्पणियाँ हैं जो मैं करना चाहता हूँ।

मैंने अप्रैल की मौद्रिक नीति के दौरान भी इसी तरह की कुछ टिप्पणियाँ की थीं, जब हम पिछली बार मिले थे। अब, मैं आज की मौद्रिक नीति के कुछ मुख्य बिंदुओं पर संक्षेप में बात करना चाहूँगा।

पहला, हमने चालू वर्ष के लिए विकास दर के अपने अनुमान को 7.2 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा है।

दूसरा, जहाँ तक मुद्रास्फीति का प्रश्न है, हमने अपने अनुमान को संशोधित किया है और अब हम पूरे वर्ष 2022-23 के लिए 6.7 प्रतिशत मुद्रास्फीति का अनुमान लगा रहे हैं। इसके अंतर्गत, तीन या चार ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

i) पहली बात यह है कि हमारे महंगाई के अनुमान में जो बढ़ोतरी हुई है - अप्रैल में हमने जो अनुमान लगाया था, उसकी तुलना में - उसका 75 प्रतिशत हिस्सा खाने-पीने की चीजों की महंगाई की वजह से है। यह बात मैंने अपने वक्तव्य में भी कही थी। कुल मिलाकर, अगर आप देखें - टमाटर की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी या राज्यों द्वारा घरेलू बिजली के टैरिफ में

किए गए कुछ बदलावों जैसे कारकों को छोड़ दें - तो खाने-पीने की चीजों की महंगाई में यह उछाल मुख्य रूप से बाहरी कारकों से जुड़ा है, खासकर यूरोप में चल रहे युद्ध से। महंगाई के मामले में यह पहला बिंदु है।

ii) दूसरी बात यह है कि हमने जो अनुमान जारी किया है, वह 'बेसलाइन सिनेरियो' (आधारभूत परिदृश्य) है; इसमें हमने आज उठाए गए कदमों को शामिल नहीं किया है।

iii) तीसरी बात, हमारा मानना है कि हमारे कदमों का प्रभाव महंगाई और महंगाई की उम्मीदों को कम करने पर पड़ेगा। हम महंगाई और महंगाई की उम्मीदों को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

iv) चौथी बात, हमारी ब्याज दरों से जुड़ी कार्रवाई और अन्य कदम, महंगाई और आर्थिक विकास की बदलती गतिशीलता के हिसाब से तय किए गए हैं। महंगाई का नीचे आना जरूरी है। साथ ही, आर्थिक सुधार की प्रक्रिया भी जारी रहनी चाहिए।

तो, मैंने आर्थिक विकास की बात की, मैंने महंगाई की बात की; ये दो मुख्य बिंदु थे।

तीसरा बिंदु जो मैं ब्याज दरों में बढ़ोतरी और हमारे 'रुख' के बारे में बताना चाहूंगा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला तो बिल्कुल स्पष्ट था - यह 50 आधार अंक की बढ़ोतरी है। इस बढ़ोतरी के बाद, रेपो रेट अब 4.9 प्रतिशत हो गया है। हमने यह बात बिल्कुल साफ-साफ कही है। जहां तक हमारे 'रुख' की बात है, जैसा कि आपने गौर किया होगा, हमने अपने वक्तव्य से यह वाक्य हटा दिया है कि 'हमारा रुख अभी भी निभावकारी बना हुआ है'। ऐसा हमने मुख्य रूप से बाजार को और अधिक स्पष्टता देने के लिए किया है। अब हमारा पूरा ध्यान इस निभावकारी रुख' को धीरे-धीरे वापस लेने पर केंद्रित है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब हम पूरी तरह से इस 'निभावकारी रुख' को वापस लेने पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ब्याज दरों के मामले में, हम अभी भी महामारी से पहले के स्तर से नीचे हैं। जहां तक बाजार में चलनिधि चलनिधि (नकदी की उपलब्धता) का प्रश्न है, तो बाजार में अभी भी महामारी से पहले के स्तर की तुलना में अधिक चलनिधि मौजूद है। इस लिहाज से देखें, तो हमारा 'रुख' अभी भी निभावकारी बना हुआ है। लेकिन अब हमारा पूरा ध्यान इस 'नरम रुख' को वापस लेने पर केंद्रित है; और इससे बाजार को, सभी संबंधित हितधारकों को, और आप सभी लोगों को - जो इस विषय पर विश्लेषण कर रहे हैं और लिख रहे हैं - और अधिक स्पष्टता मिलती है।

चौथा पॉइंट चलनिधि (तरलता) से जुड़ा है। सीआरआर को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं।

हमने सीआरआर सीआरआर नहीं बढ़ाया है। आगे चलकर, चलनिधि में कमी सोच-समझकर और नपे-तुले तरीके से की जाएगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्पादक जरूरतों को पूरा

करने के लिए पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध हो; यानी अर्थव्यवस्था की क्रेडिट जरूरतों - खास तौर पर बैंक क्रेडिट जरूरतों - को पूरा किया जा सके।

पांचवां और आखिरी पॉइंट, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में बहुत साफ तौर पर बताया है, रिज़र्व बैंक किसी भी तरह की पुरानी सोच या रीतियों से बंधा हुआ नहीं है। रिज़र्व बैंक अपने नज़रिए में हमेशा गतिशील और व्यावहारिक बना रहेगा।

मैं यहीं रुकूंगा और अब हम आपके सवालों के जवाब देंगे। अब बारी आपकी है, योगेश।

योगेश दयाल:

सर, अपनी शुरुआती टिप्पणियों के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले, मैं पीटीआई से श्री हितेश व्यास को अपना प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

हितेश व्यास, पीटीआई:

नमस्कार, यह देखते हुए कि पूरे वर्ष के लिए आपका महंगाई का अनुमान 6.7 प्रतिशत है, क्या आरबीआई दरों में बढ़ोतरी के मामले में - खास तौर पर बढ़ोतरी की मात्रा के मामले में - आक्रामक रुख अपनाएगा?

शक्तिकांत दास:

जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया है, और जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है, हमारी भविष्य की कार्रवाई महंगाई और आर्थिक विकास के बदलते समीकरणों पर निर्भर करेगी। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्थिति किस दिशा में आगे बढ़ती है।

हितेश व्यास, पीटीआई:

सीबीडीसी के मोर्चे पर, क्या इसे लॉन्च करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है? इसके संभावित माध्यम - उदाहरण के लिए, वितरण के तरीके - क्या होंगे?

शक्तिकांत दास:

मैं उप गवर्नर श्री रबी शंकर से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रश्न का जवाब दें।

टी. रबी शंकर:

समय-सीमा के बारे में बात करें तो, बजट में यह घोषणा की गई थी कि इसे इसी वर्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं बस एक बात पर ज़ोर देना चाहूंगा कि इसे पेश करने की प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी, ताकि बैंकिंग व्यवस्था या पूरी वित्तीय प्रणाली में किसी भी तरह की कोई बाधा या रुकावट न आए।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं इन्फार्मिस्ट मीडिया के श्री बिजोय इडिचेरियाह से बात करूँगा।

टी. बिजोय इडिचेरियाह, इन्फार्मिस्ट मीडिया:

आपने संकेत दिया है कि दिसंबर तक, आपको उम्मीद है कि महंगाई 6.0 प्रतिशत की सीमा से ऊपर रहेगी। इसका मतलब है कि पूरे वर्ष, आप 2.0 - 6.0 प्रतिशत के तय दायरे का उल्लंघन करेंगे। इस दायरे को पूरा करने के मामले में 'विफलता' का क्या मतलब है? आपको किस तरह की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा? और क्या इसका मतलब यह होगा कि आरबीआई को पहले से ही कदम उठाने होंगे - शायद चलनिधि वापस लेने के मामले में, या शायद दरों में बढ़ोतरी की गति के मामले में - ताकि महंगाई को वापस तय दायरे में लाया जा सके?

शक्तिकांत दास:

अभी जो बेहद अनिश्चित हालात हैं, और भविष्य के बारे में जो बेहद अनिश्चित अनुमान हैं, उन्हें देखते हुए, आप जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं, उस पर पहले से कोई पक्की जानकारी देना संभव नहीं है; यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हालात कैसे बदलते हैं। जहाँ तक आप जिस बात को 'महंगाई के लक्ष्य के दायरे का उल्लंघन' वगैरह कह रहे हैं, उसका प्रश्न है - जब भी ऐसी स्थिति आएगी, हम उससे निपटेंगे। हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, इसलिए मैं इस बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाना चाहूँगा। कानून बहुत स्पष्ट है, और हम उसी के अनुसार काम करेंगे। आज की तारीख में, मैं यह अंदाज़ा नहीं लगाना चाहूँगा कि ऐसा होगा और फिर हम वैसा करेंगे। अंदरूनी तौर पर, हम अलग-अलग स्थितियों में, अलग-अलग दिशाओं में सभी संभावनाओं की जाँच करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है - और मैं फिर दोहरा रहा हूँ - कि यह बदलते हुए हालात पर निर्भर करेगा।

टी. बिजोय इडिचेरियाह, इन्फार्मिस्ट मीडिया:

क्या इसी वजह से आपने अपना 'रुख' भी बदल दिया है? क्योंकि श्री वर्मा भी पिछली कुछ नीति बैठकों से यही कहते आ रहे हैं कि ऐसे हालात में कोई पक्का 'रुख' तय करना बहुत मुश्किल होगा।

शक्तिकांत दास:

हमारा एक 'रुख' है। मैंने अपने वक्तव्य में भी यह बात कही है, और हमारा 'रुख' है - 'निभावकारी रवैये को धीरे-धीरे वापस लेना'।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं सीएनबीसी टीवी18 की सुश्री लता वेंकटेश की ओर रुख करूँगा।

लता वैकटेश, सीएनबीसी टीवी18:

अपने भाषण में, आपने कहा कि आप एक संतुलित तरीके से सामान्य मौद्रिक स्थितियों को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि 'सामान्य' से आपका क्या तात्पर्य है? क्या यह 5.15 प्रतिशत है, जो महामारी से पहले का स्तर था? क्या यह 6.0 प्रतिशत है, जो उस समय का स्तर था जब आपने 'तटस्थ' (neutral) रुख से हटकर 'निभावकारी' का रुख अपनाया था? या फिर क्या यह 'शून्य वास्तविक दर' है, जिसका अर्थ है कि एक वर्ष की मुद्रास्फीति दर 6.7 प्रतिशत होगी? यदि ऐसा है, तो रेपो दर को मौजूदा स्तर से काफी अधिक रखना होगा।

जिस तरह से मैं 'सामान्य' को देखता हूँ - मैं और आरबीआई में मेरे सहयोगी - और जिस प्रकार से आरबीआई 'सामान्य' स्थितियों को देखता है (और एमपीसी भी), वह यह है कि अगर आपको फरवरी 2020 का मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क याद हो, जिसकी हमने घोषणा की थी, तो वह ओवरनाइट दरों से जुड़ा हुआ है। अहम बात चलनिधि की मात्रा या कोई खास स्तर नहीं होगा। हमने कोई अनुमान नहीं लगाया है, न ही हमने यह कहा है कि यह 'सामान्य दर' है; 'सामान्य दर' का मतलब है 'नीतिगत दर'। हमने बस इतना कहा है कि जब ओवरनाइट दरें, रेपो दर के साथ तालमेल में आ जाएँ। अभी भी ओवरनाइट दरें, रेपो दर से नीचे हैं। वे एसडीएफ दर के ज़्यादा करीब हैं। तो, 'सामान्य स्थिति' का मतलब मुख्य रूप से यह होगा कि जब ओवरनाइट कॉल मनी मार्केट की दरें, नीतिगत रेपो दर के साथ लगभग एक जैसे हो जाएँ।

लता वैकटेश, सीएनबीसी टीवी18:

'वास्तविक दर' के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आरबीआई की सोच क्या है? क्या आप इसकी गणना इस सामने आए 6.7 प्रतिशत के आधार पर करते हैं? आप 'वास्तविक सकारात्मक दर' की गणना कैसे करते हैं? और क्या आप वहाँ तक पहुँचना भी चाहते हैं?

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

'वास्तविक दर' हमेशा भविष्य-उन्मुखी (फारवर्ड लुकिंग) होती है, ठीक शेष मौद्रिक नीतियों की तरह। इसलिए, आपको भविष्य में कुछ समय बाद की मुद्रास्फीति दर के अनुमान पर विचार करना चाहिए - जिसके दायरे में मौद्रिक नीति काम करती है - और फिर 'वास्तविक दर' की गणना करनी चाहिए।

लता वैकटेश, सीएनबीसी टीवी18:

लेकिन आपने हमें ति1 के आँकड़े नहीं दिए हैं; आपने हमें 12 महीने आगे के आँकड़े भी नहीं दिए हैं। क्या आपके पास कम-से-कम विव 24 की पहली छमाही के लिए कोई आँकड़े हैं?

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

नहीं, आपके पास Q4 के आँकड़े हैं, और 'मौद्रिक नीति रिपोर्ट' से आपके पास 2023-24 के आँकड़े भी हैं। जैसा कि गवर्नर साहब ने कहा, आपको हालात को समझते हुए ही आगे बढ़ना होगा; यह एक बहुत ही गतिशील स्थिति है। हमें देखना होगा कि भविष्य में हालात किस तरह बदलते हैं।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'इकॉनॉमिक टाइम्स' से श्री गोवर्धन रंगन की ओर रुख करूँगा।

एम. गोवर्धन रंगन, इकॉनॉमिक टाइम्स:

दरें बढ़ाने के बावजूद, आपने उल्लेख किया है कि चलनिधि बनी रहेगी, और अतिरिक्त चलनिधि को कई सालों के समय-सीमा में वापस लिया जाएगा। तो, कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो अनुमान लगा रहे हैं कि वर्ष के आखिर तक चलनिधि न्यूट्रल हो जाएगी। तो, क्या आपके वक्तव्य का मतलब यह है कि आप यह पक्का करेंगे कि एसडीएफ का इस्तेमाल होता रहे और अगले एक या दो सालों तक एसडीएफ में फंड आते रहें, भले ही आप अकोमोडेशन (सहूलियत) वापस लेने पर फोकस कर रहे हों?

शक्तिकांत दास:

बहु वर्षीय अवधि-चक्र का मूल रूप से मतलब यह है कि हमने पिछले वर्ष ही चलनिधि वापस लेना शुरू कर दिया था। हमने जी-सैप्स(G-SAPs) रोक दिए थे। दूसरे शब्दों में, हमने कोई नया जी-सैप(G-SAP) घोषित नहीं किया। हमने पिछले वर्ष वीआरआरआर भी शुरू किए थे, यानी वेरिबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन। इस वर्ष भी हमने कदम उठाए हैं। फिर से, वीआरआरआर जारी रखे जा रहे हैं। मई के नीतिगत वक्तव्य में, हमने सीआरआर भी बढ़ाया था। बहु-वर्षीय का मूल रूप से मतलब होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा है, 2-3 वर्ष का चक्र। तो, जब आप 2-3 वर्ष कहते हैं, तो यह फिर से बहुत उदार होता है। स्थिति बहुत गतिशील है। यह तर्क दिया जा सकता है कि हमने पिछले वर्ष शुरू किया था, इसलिए पिछला वर्ष वर्ष 1 है, यह वर्ष वर्ष 2 है, अगला वर्ष वर्ष 3 है; लेकिन इन बेहद अनिश्चित स्थितियों में, हम बस यह बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम यह सब अचानक, एकदम से, या मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही जल्दबाज़ी में कर रहे हैं।

एम. गोवर्धन रंगन, इकॉनॉमिक टाइम्स:

तो, मल्टी-ईयर का आधे से ज़्यादा हिस्सा तो पहले ही बीत चुका है।

शक्तिकांत दास:

हम बस यह बताना चाहते थे कि हम कोई भी अचानक, जल्दबाज़ी वाला कदम नहीं उठाना चाहते, जो सिस्टम, मार्केट या क्रेडिट ऑफ़टेक के लिए किसी भी तरह से नुकसानदायक हो।

एम. गोवर्धन रंगन, इकोनॉमिक टाइम्स:

महंगाई के अनुमान के बारे में, आपने उन कुछ कदमों का उल्लेख नहीं किया है जो आपने उठाए हैं, जिनमें आज दरों में की गई बढ़ोतरी भी शामिल है। तो, अगर आप इस बात को और शायद सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपायों को भी ध्यान में रखते हैं, तो अगले वित्तीय वर्ष के लिए महंगाई का दृष्टिकोण कैसा दिखता है - जिस पर आपने अभी तक बात नहीं की है? अगर इन ब्याज दरों में बदलाव का प्रभाव उस पर पड़ने वाला है, तो वह दृष्टिकोण कैसा दिखाई देता है?

आप जानते हैं कि हर काम होने में समय लगता है। मौद्रिक नीति के कार्यों को पूरी तरह से प्रभाव दिखाने में, आम तौर पर 6 से 8 महीने लगते हैं। हम बदलते हालात पर नज़र रखेंगे और अगले वर्ष के महंगाई के आंकड़े मौद्रिक नीति रिपोर्ट में दिए जाएंगे। अगली रिपोर्ट अक्टूबर में आने वाली है। इसलिए, हम उस समय ये आंकड़े देंगे।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं ब्लूमबर्ग से श्री अनूप रॉय को बुलाऊंगा।

अनूप रॉय, ब्लूमबर्ग:

आपने महंगाई के बीच के बिंदु पर वापस आने के अपने लक्ष्य का उल्लेख किया था। अब, जबकि आपने महंगाई के अनुमान को इतना बढ़ा दिया है, तो क्या आपकी गणना में बीच का बिंदु बदल गया है? क्या अब आप 6.0 प्रतिशत के आसपास का लक्ष्य रख रहे हैं? और जैसा कि डॉ. पात्रा ने हाल ही में लिखा था, क्या महामारी के बाद भारत में महंगाई की सीमा बढ़ गई है?

शक्तिकांत दास:

चूंकि आप डॉ. पात्रा और उनकी लिखी बातों का उल्लेख कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का जवाब डॉ. पात्रा ही देंगे।

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

असल में, आप मेरी बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। यह गवाह को गुमराह करने जैसा मामला है। मेरा पेपर मेरे पास ही है, और मैंने उसमें यह लिखा है कि मौद्रिक नीति जिन भी पैमानों पर काम करती है - जैसे कि लक्ष्य, सीमा वगैरह - उन सभी का महामारी के आंकड़ों के आधार पर फिर से आकलन करने की ज़रूरत है; बस इतनी ही बात है।

योगेश दयाल:

अब मैं बिज़नेस स्टैंडर्ड से मनोजित साहा को अपना प्रश्न पूछने के लिए बुलाऊंगा।

मनोजित साहा, बिज़नेस स्टैंडर्ड:

जब मौद्रिक नीति को सख्त किया जाता है, तो यह तब सबसे ज़्यादा प्रभावदार होती है, जब बाज़ार में चलनिधि (नकदी) की कमी हो। क्या आपको आगे चलकर चलनिधि की कमी वाला कोई माहौल बनता दिख रहा है? यह मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यह है कि मुझे प्रस्ताव में 4.0 प्रतिशत का महंगाई लक्ष्य कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या आपके मन में 4.0 प्रतिशत के महंगाई लक्ष्य पर वापस लौटने का कोई विचार है? या फिर, आप फिलहाल 6.0 प्रतिशत के स्तर पर ही बने रहने में सहज महसूस कर रहे हैं?

श्री शक्तिकांत दास:

ठीक यही प्रश्न अभी अनूप राँय ने पूछा था और हमने कहा है कि हमारी कोशिश लक्ष्य के करीब पहुँचने की होगी। और वह लक्ष्य है 4.0 प्रतिशत, जिसमें दोनों तरफ 2.0 प्रतिशत की घट-बढ़ (प्लस या माइनस) हो सकती है। तो, 4.0 प्रतिशत का वह लक्ष्य बना रहेगा।

चलनिधि पर कई अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। सरकारी खर्च की गति, उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा किया जाने वाला शुरुआती पूंजीगत खर्च जैसा कि पिछले वर्ष हुआ था - अगर इस वर्ष भी पूंजीगत खर्च और अन्य खर्चों को शुरुआत में ही कर दिया जाता है, तो इससे चलनिधि बढ़ती है। क्रेडिट ऑफ़टेक (ऋण उठाव), जिसमें अब सुधार हुआ है - जैसा कि हमने अपने प्रस्ताव में भी उल्लेख किया है। इसमें 12.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अगर यह बढ़ोतरी बनी रहती है, तो ज़ाहिर है कि सिस्टम से चलनिधि बाहर जाएगी। विदेशी मुद्रा बाज़ार से जुड़े कुछ अन्य कारक भी हैं, जो चलनिधि को बढ़ाते या घटाते हैं। यह एक लगातार बदलती रहने वाली स्थिति है। हम बस इतना कह रहे हैं कि हम पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। अगर चलनिधि में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है—जैसा कि आपका प्रश्न है - तो रेपो विंडो हमेशा उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल सिस्टम द्वारा किया जा सकता है।

लता वैकटेश, सीएनबीसी टीवी18:

उनकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए, आपने कोई भी खास बात नहीं कही है; चलनिधि से जुड़ा कोई भी खास उपाय घोषित नहीं किया गया है - न तो सीआरआर, और न ही कोई अन्य उपाय। तो, क्या हमें यह समझना चाहिए कि अब से चलनिधि को नियंत्रित करने के लिए नकद निकासी और विदेशी मुद्रा बिक्री की सामान्य प्रक्रिया ही काफी होगी?

शक्तिकांत दास:

बेहद अस्थिर और अनिश्चित परिस्थितियों में, हम कोई भी 'फॉरवर्ड गाइडेंस' (भविष्य के लिए कोई निश्चित संकेत) नहीं दे सकते। हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। असल में, 'रियल-टाइम' (तत्काल) आधार पर, रिज़र्व बैंक की पूरी टीम स्थिति पर नज़र रख रही है और हम आवश्यक कदम उठाएँगे। अगर आपको याद हो, तो अपना वक्तव्य पढ़ते समय मैंने एक जगह थोड़ा

विराम लिया था - जब मैं इस वर्ष सरकारी उधार कार्यक्रम को बिना किसी बाधा के लागू करने के बारे में बात कर रहा था। मैंने एक पल का विराम लिया और समझाया कि मैंने यह नहीं कहा है कि आरबीआई द्वारा कौन-से कदम उठाए जाएँगे; बल्कि, बदलती हुई स्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार, हम उन विभिन्न साधनों का उपयोग करेंगे जो हमारे पास उपलब्ध हैं।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं रॉयटर्स से स्वाति भट शेट्टे की ओर रुख करूँगा।

स्वाति भट शेट्टे, रॉयटर्स:

गवर्नर साहब, क्या आप हमें इस बारे में थोड़ी और स्पष्टता दे सकते हैं कि सबसे पसंदीदा कदम क्या है?

आज आपने जो वक्तव्य दिया, उससे बाज़ारों को साफ़ तौर पर बहुत राहत मिली। हमने देखा है कि बॉन्ड यील्ड लगभग 10 से 12 आधार अंक नीचे आ गई है। इस समय सबसे पसंदीदा कदम क्या है? क्या सरकार के उधार कार्यक्रम को संभालने के मामले में कोई पसंदीदा उपाय हैं? यह देखते हुए कि आप 'निभावकारी उपाय की वापसी' के दौर में हैं, आप बाज़ार में और ज़्यादा चलनिधि डालना नहीं चाहेंगे? तो, आप इसे कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं?

शक्तिकांत दास:

पसंदीदा कदम इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस स्थिति में हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि हम जी-सेक बाज़ारों पर नज़र रख रहे हैं; असल में, हम सभी बाज़ारों पर नज़र रखते हैं। जी-सेक बाज़ार पर भी हम बहुत बारीकी से नज़र रख रहे हैं। पसंदीदा कदम फिर से उस समय की मौजूदा स्थिति पर निर्भर करेगा। आप जानते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से साधन उपलब्ध हैं। 'ऑपरेशन ट्विस्ट' के संबंध में, आज हमारे पास ज़्यादा ताकत और ज़्यादा लचीलापन है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त प्रतिभूतियां हैं। एसडीएफ की शुरुआत के कारण, स्वाभाविक रूप से जो प्रतिभूतियां हमारे पास उपलब्ध हैं - जो कि पहले के संदर्भ में, अगर रिवर्स रेपो होता, तो हमें प्रतिभूतियां देनी पड़तीं - आज हमारे पास 'ऑपरेशन ट्विस्ट' करने के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियां हैं। यह सिर्फ़ एक तथ्यात्मक जानकारी है; मैं कोई 'फॉरवर्ड गाइडेंस' (भविष्य के लिए कोई संकेत) नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि 'ऑपरेशन ट्विस्ट' के संबंध में आज हमारे पास ज़्यादा ताकत है और हमारे पास अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने के लिए अन्य साधन भी उपलब्ध हैं। अगर आरबीआई में हमारी टीम चलनिधि की समस्या से निपटने के लिए कोई नया और अनोखा कदम लेकर आती है, तो हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन, इस समय, कोई नया कदम नहीं उठाया जा रहा है; इसलिए, इस नतीजे पर न पहुँचें

कि कोई और जी-सैप या वैसा ही कुछ और आने वाला है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं और ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी कदम उठाएँगे।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' से श्री मयूर शेट्टे की ओर रुख करूँगा।

मयूर शेट्टे, टाइम्स ऑफ़ इंडिया:

गवर्नर साहब, जैसा कि आपने बताया, लेंडिंग (कर्ज़ देने) के मामले में प्रसारण बहुत प्रभावी रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ऋण अब रेपो दर जैसे बाहरी बेंचमार्क से जुड़े हुए हैं। लेकिन डिपॉज़िट (जमा) के मामले में, यह उतना प्रभावदार नहीं रहा है। तो, क्या आपको लगता है कि इससे मौद्रिक नीति का प्रभाव कम हो जाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि लोग बचत कम करें, और निवेश भी न करें, क्योंकि लेंडिंग दर बढ़ रहे हैं?

शक्तिकांत दास:

हमने अक्टूबर 2019 में, यानी अब से दो वर्ष पहले, यह बाहरी बेंचमार्किंग शुरू की थी। हम इसकी निगरानी कर रहे हैं और आम तौर पर, इसका प्रभाव दिखने में समय लगता है। हमने अभी लगभग एक महीने पहले ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसका प्रभाव दिखने में लगभग 1-3 महीने लगते हैं, इसलिए इसमें समय लगेगा। लेकिन, आगे चलकर, हमें उम्मीद है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का प्रभाव देयता पक्ष पर भी दिखेगा, यानी जमा दरों पर भी। मैंने अपने वक्तव्य में भी यह बात मानी है कि बैंक जमा दरें बढ़नी शुरू हो गई हैं। वैसे भी, जब क्रेडिट ऑफ़टेक (कर्ज़ लेने की मांग) बढ़ता है, तो बैंकों को बचत करने वालों को ज़्यादा जमा दरें देकर ज़्यादा संसाधन जुटाने की ज़रूरत होती है।

मयूर शेट्टे, टाइम्स ऑफ़ इंडिया:

आवर्ती जनादेश (रिकरिंग मेंडेट्स) के मामले में, आपने घरेलू भुगतानों के लिए ₹15,000 की सीमा में छूट दी है। लेकिन लोगों को अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इनमें से कई सेवा प्रदाता के लिए, भारत एक बहुत छोटा बाज़ार है, इसलिए वे आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं।

शक्तिकांत दास:

मुझे आपका प्रश्न समझ आ गया। प्रश्न का पहला हिस्सा, जो ब्याज दरों के प्रभाव से जुड़ा है, अगर उप गवर्नर माइकल पात्रा उसमें कुछ जोड़ना चाहें, तो जोड़ सकते हैं। लेकिन आपके प्रश्न का दूसरा पहलू, उप गवर्नर रबी शंकर को संभालने दीजिए।

टी. रबी शंकर:

1 अक्टूबर से, जब हमने यह व्यवस्था शुरू की थी, तब से अब तक लगभग 5.9 करोड़ मैडेत्स रजिस्टर हो चुके हैं। कुल मैडेत्स की संख्या लगभग 6.5 करोड़ है, जिसका सीधा सा मतलब है कि लगभग 0.6 करोड़ मैडेत्स पहले से मौजूद थे, और उसके बाद इतने और मैडेत्स रजिस्टर किए गए हैं। असल में, हमें इससे हैरानी हुई, क्योंकि हमें लगा था कि कुल उपलब्ध मैडेत्स की संख्या लगभग 5.0 करोड़ के आसपास होगी। लेकिन यह उससे कहीं ज़्यादा है। तो, शायद इसका एक बड़ा हिस्सा इसके दायरे में आ चुका है। इन मैडेत्स में, लगभग 3,450 अंतरराष्ट्रीय मर्चेत्स ने भी रजिस्टर किया है। उनमें से कुछ मर्चेत्स, जिनके लिए भारत का बाज़ार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें अपने सिस्टम को इस नई व्यवस्था के हिसाब से ढालने के लिए ज़रूरी निवेश करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। कुछ बड़े मर्चेत्स ने हमें बताया है कि वे अपने सिस्टम में बदलाव कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और तब तक कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हमने हाल ही में लिमिट बढ़ाने की घोषणा के ज़रिए कुछ बातों को सुलझाने की कोशिश की है। हमें कई लोगों से पता चला कि कई अंतरराष्ट्रीय उत्पाद, मैगज़ीन वगैरह बहुत महंगे होते हैं। इसलिए, हर बार ऐसा करना एक मुश्किल काम बन जाता है। इसलिए, इस वर्ष हमने सीमा को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया है। इससे शायद यह समस्या हल हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर आपके प्रश्न का जवाब यह है कि अभी जो संख्या और मात्रा वॉल्यूम बची हुई है, वह बहुत ज़्यादा नहीं है और समय के साथ वह भी इसमें शामिल हो जाएगी। आखिर में, उस ई-मैडेट का मकसद यह है कि ग्राहक का अपनी डिजिटल भुगतान गतिविधि पर बेहतर नियंत्रण हो; यही हमारा आखिरी लक्ष्य है और इसे हासिल कर लिया जाएगा।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं मिंट से गोपिका गोपाकुमार की ओर रुख करूँगा।

गोपिका गोपाकुमार, मिंट:

नमस्कार, गवर्नर साहब। मेरा प्रश्न दक्षिण भारत के एक निजी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक के बारे में है। एक मौद्रिक समूह, यानी शेयरधारकों के एक समूह ने एक मुद्दा उठाया है; उन्होंने एक ईजीएम (असाधारण सामान्य सभा की बैठक) बुलाने की मांग की है, यह कहते हुए कि बैंक में वित्तीय संकट है। बोर्ड में निदेशकों की संख्या भी कम हो गई है। क्या यह चिंता का विषय है? क्या आरबीआई इस पर ध्यान दे रहा है?

शक्तिकांत दास:

हम किसी भी एक बैंक और उसमें चल रही स्थितियों पर बाहर, और खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए, मैं किसी भी एक बैंक पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जैसा

कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली विभिन्न महत्वपूर्ण पैमानों जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी (पूँजी पर्याप्तता), प्रोविजनिंग, प्रॉफिटेबिलिटी और अनर्जक आस्तियों के मामले में मज़बूत और स्थिर बना हुआ है। पिछले तीन सालों में हमारी निगरानी का दायरा काफी गहरा हुआ है। हमारे बैंकिंग प्रणाली के हर एक बैंक पर बहुत बारीकी से नज़र रखी जाती है। हमारे पास रियल-टाइम डेटा उपलब्ध है, और हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। हमारे सुपरवाइजरी अधिकारी हर बैंक की स्थिति पर बहुत-बहुत बारीकी से नज़र रख रहे हैं। कुल मिलाकर, भारतीय बैंकिंग प्रणाली मज़बूत और स्थिर बनी हुई है।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस से श्रीतमा बोस की ओर रुख करूँगा।

श्रीतमा बोस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस

नमस्कार, सर। तो, एक प्रश्न टोकनीकरण पर है। आपको क्या लगता है कि इस पर कितनी प्रगति हुई है? क्या 30 जून की डेडलाइन को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है? दूसरा प्रश्न RuPay क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के बारे में है। क्या इस बारे में कोई अंदाज़ा है कि इसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, क्योंकि अभी यूपीआई और क्रेडिट कार्ड बिल्कुल अलग-अलग एमडीआर ढांचे पर काम करते हैं?

शक्तिकांत दास:

उप गवर्नर, रबी शंकर इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।

टी. रबी शंकर:

सबसे पहले टोकनीकरण पर - लगभग तीन हफ़्ते बाकी हैं, और प्रगति संतोषजनक रही है। पिछले कुछ महीनों से हमारी टीम सभी हितधारकों के साथ लगातार बातचीत कर रही हैं ताकि यह पक्का हो सके कि टोकनीकरण की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो और सिस्टम मोटे तौर पर तैयार हो जाए। सभी कार्ड नेटवर्क टोकनीकरण की सुविधा दे रहे हैं। पिछली गिनती के हिसाब से लगभग 16 करोड़ टोकन पहले ही बन चुके हैं, और जैसे-जैसे हम अंतिम तारीख के करीब पहुँचेंगे और डेडलाइन के बाद भी, यह संख्या और बढ़ेगी। यह ज़रूरी नहीं है कि अंतिम तारीख से पहले ही हर किसी के पास टोकन हो, आप बाद में भी ऐसा कर सकते हैं। तो, सिस्टम तैयार है। मुझे सच में नहीं लगता कि इस बात पर अटकलें लगाने की कोई ज़रूरत है कि अंतिम तारीख बढ़ाई जाएगी या नहीं। कुछ छोटे-मोटे मुद्दे हमारे संज्ञान में आए हैं, जिन्हें हम समय के साथ ठीक कर लेंगे। ये नए मुद्दे हैं जो हर बार जब आप कोई नया सिस्टम लागू करते हैं तो सामने आते हैं। हम समय के साथ इन्हें हल कर लेंगे। तो कुल मिलाकर, मैं इसे संतोषजनक ही कहूँगा।

श्रीतमा बोस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस

क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के बारे में दूसरा प्रश्न।

टी. रबी शंकर:

प्राइसिंग स्ट्रक्चर पर अभी बात करना जल्दबाजी होगी। हम देखेंगे कि इसकी प्राइसिंग कैसे तय होती है। क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने का मुख्य मकसद ग्राहक को भुगतान के ज़्यादा विकल्प देना है। अभी, यूपीआई डेबिट कार्ड के ज़रिए बचत बैंक खाता या चालू खाता से जुड़ा होता है। अब, इसे उस क्रेडिट कार्ड खाता से जोड़ा जा सकता है जो बैंक आपको देते हैं, जिससे ग्राहक के पास मौजूद विकल्पों में सुधार होता है। इसकी प्राइसिंग कैसे तय होगी, यह हमें देखना होगा, क्योंकि प्राइसिंग तय करने का काम बैंकों और सिस्टम से जुड़ी संस्थाओं को ही करना होगा। इस समय, हम इस व्यवस्था को पेश कर रहे हैं। प्राइसिंग के मामले में, हम देखेंगे कि आगे क्या होता है।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'द हिंदू बिजनेस लाइन' से सुरभि प्रसाद की ओर रुख करूँगा।

सुरभि प्रसाद, द हिंदू बिजनेस लाइन:

आरबीआई ने महंगाई को लेकर कई कदम उठाए हैं, और केंद्र सरकार ने भी ऐसा ही किया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सप्लाइ-साइड उपायों (आपूर्ति पक्ष के उपायों) की ओर भी ज़रूरत है, खासकर शायद ईंधन टैक्स के मामले में फिर से कुछ करने की? मेरा दूसरा प्रश्न क्रिप्टोकॉरेंसी को लेकर है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि वे जल्द ही एक कंसल्टेशन पेपर (परामर्श पत्र) जारी करने वाले हैं। तो, क्या इस मुद्दे पर आगे कोई बातचीत हुई है? धन्यवाद।

शक्तिकांत दास:

क्रिप्टोकॉरेंसी के बारे में मैं यह कह सकता हूँ कि सभी मुद्दों पर सरकार और आरबीआई के बीच लगातार बातचीत होती रहती है, जिसमें क्रिप्टोकॉरेंसी से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। हमने सरकार को अपने विचार बता दिए हैं। चलिए, अब चर्चा पत्र का इंतज़ार करते हैं। जहाँ तक दूसरे पहलू की बात है, जिसका उल्लेख आपने किया था - यानी सप्लाइ-साइड उपायों की - तो अब इस पर फ़ैसला सरकार को लेना है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार मौजूदा महंगाई की स्थिति से पूरी तरह वाकिफ़ है, और आगे के सप्लाइ-साइड उपायों पर फ़ैसला लेना सरकार का काम है - ऐसे उपाय, जिन्हें वे ज़रूरी समझते हैं। इस बारे में मैं कोई अटकल नहीं लगाना चाहूँगा, और न ही इस पर कोई टिप्पणी करना चाहूँगा। फ़ैसला सरकार को ही लेना है, और मुझे यकीन है कि वे ज़रूरत पड़ने पर - जब भी उन्हें लगेगा कि इसकी ज़रूरत है - ज़रूर कदम उठाएँगे।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'बी क्यू प्राइम' से विश्वनाथ नायर की ओर रुख करूँगा।

विश्वनाथ नायर, 'बी क्यू प्राइम':

नमस्कार, गवर्नर साहब। मेरा प्रश्न उन उपायों से जुड़ा है, जिनकी घोषणा आपने अपने वक्तव्य के दौरान सहकारी बैंकों के संदर्भ में की थी। इसके दो हिस्से हैं: पहला - आरबीआई सहकारी प्रणाली का इस्तेमाल करके मांग को और बढ़ाने में कितना सहज महसूस करता है? क्योंकि अब आप उन्हें ज्यादा होम ऋण (गृह ऋण) देने की अनुमति दे रहे हैं। और दूसरा हिस्सा - उन्हें कमर्शियल रियल एस्टेट (वाणिज्यिक स्थावर संपदा) के क्षेत्र में उतरने की अनुमति देने से जुड़ा है। इसके विनियमन और पर्यवेक्षण वाले हिस्से को लेकर आप कितने सहज हैं? क्योंकि अतीत में यह एक बड़ी चुनौती रहा है, खासकर वाणिज्यिक स्थावर संपदा के मामले में। तो, मैं बस यही जानना चाहता था।

शक्तिकांत दास:

उप गवर्नर, राजेश्वर राव इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।

राजेश्वर राव:

ग्राहक की मांग असल में उस उपाय से पैदा नहीं होती जिसकी हमने घोषणा की है। असल में, ग्राहक की मांग उस उपाय से पूरी होती है जिसकी हमने घोषणा की है। बैंकों के पास अपने ग्राहक की हाउसिंग ऋण या ज्यादा रकम वाले हाउसिंग ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा उदारता है। तो यही चीज़ मुमकिन बनाई जा रही है। और हाँ, ये सब कुछ सुरक्षा उपायों के तहत हैं, जैसे कि ऋण की ऊपरी सीमा तय करना, लिमिट तय करना वगैरह। तो, इससे उस बड़े जोखिम का ध्यान रखा जाएगा जो इस उपाय से पैदा हो सकता है, अगर आपको लगता है कि कोई जोखिम है। जैसा कि गवर्नर पहले ही बता चुके हैं, हमारे पास सभी बैंकिंग संस्थाओं और बैंकिंग यूनिट्स की बहुत बारीकी से निगरानी करने की एक प्रणाली है। हम बैंकों की कमज़ोरियों का बहुत बारीकी से आकलन करने और हालात पर नज़र रखने की स्थिति में हैं। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के उपाय से पैदा होने वाले किसी भी जोखिम को लेकर ज्यादा चिंता की कोई बात होगी।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं जी बिजनेस न्यूज से अनुराग शाह को आमंत्रित करता हूँ।

अनुराग शाह, जी बिजनेस न्यूज:

मेरा प्रश्न डिजिटल लेंडिंग ऐप्स से जुड़ा है। क्या रिज़र्व बैंक इस मामले में दूसरी एजेंसियों के साथ भी मिलकर काम कर रहा है? क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि ज़बरदस्ती वसूली

वगैरह के कई मामले सामने आए हैं। अकेले मुंबई में ही, डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की तरफ से की जा रही परेशानियों से तंग आकर कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। आम लोगों में यह धारणा है कि डिजिटल लेंडिंग ऐप्स का रेगुलेशन रिज़र्व बैंक ही करता है। तो, आप किन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? और पिछले वर्ष जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था, उस पर अब तक कितनी प्रगति हुई है?

शक्तिकांत दास:

आपने डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के ज़रिए ऋण देने और उससे जुड़ी अलग-अलग तरह की समस्याओं के बारे में जो बताया, उनमें से ज्यादातर ऐप्स बिना पंजीकरण वाले हैं। इसका मतलब है कि वे अपने आप काम कर रहे हैं और आरबीआई के साथ पंजीकृत नहीं हैं। इसलिए, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, उस पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों, जैसे कि राज्य पुलिस या दूसरी एजेंसियों को कार्रवाई करनी चाहिए, और वे ऐसा कर भी रही हैं। शिकायतें दर्ज हो रही हैं और वे कार्रवाई कर रहे हैं। जब हमें कोई शिकायत मिलती है, तो हम तुरंत ग्राहक या शिकायत करने वाले व्यक्ति को सलाह देते हैं कि वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएँ; कई मामलों में राज्य पुलिस ने प्रभावदार कार्रवाई की है। आपने एक रिपोर्ट का उल्लेख किया है; वह रिपोर्ट हमारे पास पहुँच गई है। यह रिपोर्ट इन डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी मुश्किलों और चुनौतियों के बारे में है। इस रिपोर्ट की जाँच का काम काफी आगे बढ़ चुका है। इस पर कई टिप्पणियाँ आई हैं। जब से यह रिपोर्ट आई है, तब से कई नए घटनाक्रम हुए हैं। इसकी जाँच का काम काफी आगे बढ़ चुका है। हम इसकी जाँच करेंगे और ज़रूरी निर्देश और गाइडलाइंस जारी करेंगे। बिना रेगुलेशन और बिना रजिस्ट्रेशन वाले ऐप्स के मामले में, ग्राहकों को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वे रजिस्टर्ड हैं या नहीं। इसलिए, जो कोई भी इन लेंडिंग ऐप्स का इस्तेमाल करता है, मैं उनसे पूरी गंभीरता से गुज़ारिश करता हूँ कि वे सबसे पहले यह जाँच लें कि वे आरबीआई के साथ पंजीकृत हैं या नहीं। अगर वे आरबीआई के साथ पंजीकृत हैं और उनमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो आरबीआई तुरंत कार्रवाई करेगा। मैं आपको इसका भरोसा दिलाता हूँ। आजकल यह हो रहा है कि बैंकों के नाम पर भी कई मैसेज आ रहे हैं, जिनमें कहा जाता है कि अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपको तुरंत ऋण या कोई सुविधा मिल जाएगी। इसलिए, बैंकों की ओर से ग्राहकों को बार-बार मैसेज, SMS और WhatsApp के ज़रिए यह सलाह दी जा रही है कि बैंक अपने ग्राहकों से OTP नंबर या CVV नंबर जैसी कोई भी निजी जानकारी नहीं माँगते हैं। अगर ऐसा कोई संदेश आता है, तो अपने मोबाइल फ़ोन पर उस पर तुरंत क्लिक न करें; जो भी मैसेज आए, उसे ध्यान से देख लें। मैं सभी ग्राहकों से कहना चाहूंगा कि वे इस बात को नोट कर लें और अपने बैंक की ब्रांच में फोन करके पता करें कि क्या यह मैसेज सही है। अगर बैंक इसकी पुष्टि करता है, तो आप उसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं।

अनुराग शाह, जी बिजनेस न्यूज:

हाल के दिनों में, आपने पाँच एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द किए हैं, जिनके पास एक दर्जन से ज्यादा मोबाइल ऐप्स थे। क्या इन पाँचों एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द करने के पीछे भी वैसी ही कुछ गड़बड़ियाँ थीं?

शक्तिकांत दास:

कई तरह की समस्याएँ और गलतियाँ थीं, इसीलिए हमने लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया। अलग-अलग संस्थाओं के मामले में, हमने किस वजह से लाइसेंस रद्द किया, इस बारे में यहाँ कुछ भी कहना शायद सही नहीं होगा।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं ईटी नाउ के श्री अंकुर मिश्रा की ओर रुख करूँगा।

अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:

नमस्कार, गवर्नर साहब। ऐसी स्थिति में, जब महंगाई की उम्मीदें आपकी तय सीमाओं के अंदर ही हैं - जैसा कि आपने ति1 में 7.5 प्रतिशत और उसके बाद धीरे-धीरे कमी का अनुमान लगाया है - तो क्या आपकी ब्याज दर में बढ़ोतरी (अगर होती है) उसी अनुपात में होगी, या फिर उसे शुरू में ही ज्यादा कर दिया जाएगा? इसे कैसे समझा जाए, जबकि एक महीने के अंदर ही 90 आधार अंक की बढ़ोतरी हो चुकी है?

शक्तिकांत दास:

इस प्रश्न का जवाब उप गवर्नर माइकल पात्रा देंगे।

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

दरअसल, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूँ: इस वर्ष अब तक 130 आधार अंक की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि महंगाई में सिर्फ 80 आधार अंक की ही बढ़ोतरी हुई है। मैंने तो बस तथ्यों के आधार पर आपके प्रश्न का जवाब दिया है।

अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:

तो फिर, इसे कैसे समझा जाए, सर?

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

दरअसल, मैं आपको यह बताना भूल गया था कि आपको पिछले वर्ष की 20 आधार अंक की बढ़ोतरी को भी इसमें शामिल करना चाहिए, जो 'फिक्स्ड' से 'रिवर्स रेपो' में बदलाव पुनर्संतुलन

के ज़रिए की गई थी। हम तब तक काम करते रहेंगे, जब तक कि महंगाई हमारे तय लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाती या उसके अनुरूप नहीं हो जाती।

अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:

लेकिन, अगर मैं उस अनुपात की बात करूँ जिसका उल्लेख मैंने अभी किया था - यानी ऐसी स्थिति में जब महंगाई आपकी उम्मीदों के दायरे में ही रहती है - तो क्या बढ़ोतरी भी उसी अनुपात में होगी? मेरा मतलब है, क्या इसे शुरू में ही ज़्यादा कर दिया जाएगा?

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

किसी भी केंद्रीय बैंक से भविष्य की ब्याज दरों के बारे में कभी भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए।

अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:

मैं अपनी गलती मानता हूँ। सर, प्रश्न पूछना हमारा काम है। दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता था, वह एनबीएफसी के प्रावधानों से जुड़े दिशानिर्देशों के बारे में थी, जो हाल ही में जारी किए गए हैं। आपने एनबीएफसी की ऊपरी श्रेणी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। क्या यह उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरी श्रेणियों के लिए भी इसी तरह के दिशानिर्देश आएंगे?

शक्तिकांत दास:

आज हर कोई कई प्रश्न पूछ रहा है। समय की कमी को देखते हुए और सभी को मौका देने के लिए, मैं अनुरोध करूँगा कि हर कोई सिर्फ एक प्रश्न पूछे। उप गवर्नर, राजेश्वर राव इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।

राजेश्वर राव:

मानक आस्तियों के लिए प्रावधान बढ़ाने की घोषणा, असल में पिछले वर्ष 'स्केल-बेस्ड रेगुलेशन' के तहत की गई घोषणा का ही अगला कदम है, और यह उन उपायों के अनुरूप है जिनकी घोषणा हमने उस समय की थी। दूसरी संस्थाओं के लिए, हम सही समय पर उचित कदम उठाएंगे। इसलिए, हम अभी बस इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। अब मैं 'द हिंदू' से श्री ललार्तेदु मिश्र को बुलाना चाहूँगा।

ललार्तेदु मिश्र, द हिंदू:

धन्यवाद, सर। अप्रैल में हुई आपकी मौद्रिक नीति (मौद्रिक नीति) बैठक में, आपने कोविड के बाद आ रहे 'बड़े बदलावों' (टेकटॉनिक शिफ्ट) के बारे में बात की थी। हाल ही में हमने जेपी मार्गन के सीईओ को यह कहते हुए सुना कि हमारी तरफ़ एक 'तूफ़ान' (हरीकेन) आ रहा है। यहाँ तक कि एलॉन मस्क ने भी अपनी 'बहुत बुरी आशंका' के बारे में बात की थी। तो, वैश्विक

और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपका क्या आकलन है? हम इस स्थिति से निपटने के लिए कितने बेहतर या कितने बुरे हालात में हैं? धन्यवाद, सर।

शक्तिकांत दास:

इस लिहाज़ से, आरबीआई बाकी सभी से आगे है। अप्रैल की मौद्रिक नीति में, मैंने 'बड़े बदलावों' (tectonic shifts) शब्द का इस्तेमाल किया था; उसके बाद, IMF ने 'भूकंप' शब्द का इस्तेमाल किया। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति का उल्लेख कर रहे हैं जो 'तूफान' की बात कर रहा है, और किसी ऐसे व्यक्ति का जो 'बहुत बुरी आशंका' जैसी दूसरी बातों का उल्लेख कर रहा है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था मज़बूत बनी हुई है। भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। बैंकिंग क्षेत्र मज़बूत और स्थिर बना हुआ है। कुल मिलाकर, मैक्रोइकोनॉमिक (समष्टि-आर्थिक) आँकड़े भी मोटे तौर पर ठीक ही लग रहे हैं। विनिमय दरों में अब तक हुई गिरावट के मामले में, भारतीय रुपया अपने जैसे अन्य उभरते बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं और अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक है। पिछले वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटे का जो आंकड़ा तय किया गया था, उसे भी हासिल कर लिया गया है। जो भी लक्ष्य रखा गया था, उसमें वास्तव में सुधार ही हुआ है। उन्होंने 6.9 प्रतिशत का अनुमान लगाया था, जबकि राजकोषीय घाटे का आंकड़ा 6.7 प्रतिशत रहा है। इसलिए, कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था एक मज़बूत स्थिति में बनी हुई है। अर्थव्यवस्था में सुधार की गति तेज़ हो रही है, और यह इस बात से भी ज़ाहिर होता है कि उत्पादन क्षमता का उपयोग बढ़ा है, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी उल्लेख किया है। बैंकों द्वारा ऋण वितरण में भी तेज़ी आ रही है; साथ ही, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मांग में और अधिक सुधार के संकेत मिल रहे हैं। तो, हमारी मौजूदा स्थिति कुछ इस प्रकार है।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। आपकी अनुमति से, हम आखिरी दो प्रश्न लेंगे। मैं मनीकंट्रोल से सिद्धि नायक को आमंत्रित करता हूँ।

सिद्धि नायक, मनीकंट्रोल:

धन्यवाद, सर। सबसे पहले, मैं आपसे यह पूछना चाहती थी कि क्या कोई बैंकिंग प्रणाली चलनिधि सीमा है जिसे आप लक्ष्य कर रहे हैं, और अगर आगे चलकर चलनिधि वापस ली जाती है, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि मांग दर आगे चलकर एसडीएफ के बजाय रेपो दर के साथ तालमेल में होगी?

शक्तिकांत दास:

इस प्रश्न का जवाब उप गवर्नर माइकल पात्रा को देने दीजिए।

डॉ. माइकल डी. पात्रा:

अगर आपको याद हो, तो फरवरी 2020 में, महामारी शुरू होने से पहले, हमने एक संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे की घोषणा की थी। आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए एक अंतर यह था कि हमने सभी मात्रात्मक संकेतकों को हटा दिया था। जैसे कि हमारे पास पहले एनडीटीएल का 1.0 प्रतिशत और बाकी सब होता था, उसे हटा दिया गया। आप चलनिधि का अंदाज़ा दर से लगाते हैं। जैसा कि गवर्नर ने बताया, अगर मांग दर फ्लोर (निचली सीमा) पर या उससे नीचे है, तो हम अकोमोडेटिव (नरम रुख वाले) हैं; अगर यह रेपो दर के करीब है, तो हम न्यूट्रल (तटस्थ) हैं। जब यह उससे ऊपर होता है, तो इसे टाइट (कठोर) किया जाता है। अभी मांग मनी दर कॉरिडोर के फ्लोर पर है, इसलिए हम अकोमोडेटिव हैं। जो चलनिधि हर दिन अवशोषित की जाती है - यानी वह अधिशेष जो बाज़ार आरबीआई को देते हैं - वह कुल मिलाकर ₹5 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो, वहाँ भरपूर चलनिधि है। साथ ही ऋण वृद्धि भी बढ़ रही है। क्रेडिट वृद्धि असल में मांग पर निर्भर करती है। यह पहले से ही दोहरे अंकों में है, और अब तक चलनिधि इस क्रेडिट वृद्धि में कोई रुकावट या बाधा नहीं बनी है।

योगेश दयाल:

धन्यवाद, सर। मैं आखिरी प्रश्न के लिए न्यूज़ राइज़ से श्री जिगर पाठक को आमंत्रित करता हूँ।

जिगर पाठक, न्यूज़ राइज़:

इस अवसर के लिए धन्यवाद। गवर्नर साहब, आपने अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में बात की। हम व्यापार घाटे पर आपका नज़रिया जानना चाहते थे, जो अभी रिकॉर्ड ऊँचाई पर है।

शक्तिकांत दास:

व्यापार घाटा?

जिगर पाठक, न्यूज़ राइज़:

जो अभी लगभग 23 बिलियन अमरीकी \$ है। तो, व्यापार घाटे के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक का कुल मिलाकर क्या दृष्टिकोण है?

शक्तिकांत दास:

मैंने अपने वक्तव्य में इस पर बात की थी, उसमें बाहरी क्षेत्र पर एक हिस्सा है। हमें उम्मीद है कि चालू खाता घाटा एक टिकाऊ स्तर पर बना रहेगा और सामान्य प्रवाह हमें चालू खाता घाटे की फ़ाइनेंसिंग करने में मदद करेगा। कुल मिलाकर निर्यात बढ़ रहा है, आयात भी बढ़ रहा है। ज़्यादा निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है; ज़्यादा आयात भी, इस हद

तक कि अगर पूंजीगत सामानों का आयात हो रहा है - जो संयोग से बढ़ा भी है - तो यह भी एक अच्छा संकेत है; इसका मतलब है कि पूंजीगत खर्च हो रहा है। निवेश हो रहा है या होने वाला है। कुल मिलाकर, चालू खाता घाटा टिकाऊ स्तरों पर बने रहने की उम्मीद है। सामान्य प्रवाह हमें इसकी फ़ाइनेंसिंग करने में मदद करेगा।

जिगर पाठक, न्यूज़ राइज़:

यह काफी समय से 20 बिलियन अमरीकी \$ के स्तर से ऊपर बना हुआ है। तो, क्या यह चिंता का विषय है?

शक्तिकांत दास:

हम लगातार इस पर नज़र रख रहे हैं। इस समय, कृपया हमारे पास मौजूद विशाल रिज़र्व को भी ध्यान में रखें। यह 601.1 बिलियन अमरीकी \$ है। यह मेरे पास मौजूद सबसे ताज़ा आंकड़ा है। यह पिछले शुक्रवार, 3 जून का आंकड़ा था, जिसे मैंने आज अपने वक्तव्य में भी बताया है। तो, हमने मज़बूत बफ़र तैयार किए हैं, जो ऐसी स्थितियों में हमारी मदद करेंगे - अगर आपकी कही बात सच होती है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक आरबीआई की बात है, हमें उस तरह के संकट की स्थिति की कोई आशंका नहीं है। हमारे पूंजीगत बफ़र और सामान्य आवक यह सुनिश्चित करेंगे कि हम चालू खाता घाटे की फ़ाइनेंसिंग करने की स्थिति में रहें।

क्या सभी ने अपने प्रश्न पूछ लिए हैं, या कोई और भी है जो अभी कुछ पूछना चाहता है? ठीक है। मुझे लगता है कि अब आप इसे समाप्त कर सकते हैं।

योगेश दयाल:

दूसरे प्रश्न के लिए कुछ अनुरोध आए थे, लेकिन अभी हमारे पास समय की कमी है। इसलिए, अब हम इसे यहीं समाप्त करेंगे। इसी के साथ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अब समाप्त होती है। मैं रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन का यहाँ उपस्थित होने के लिए, और हमारे मीडिया साथियों का इस अत्यंत सुव्यवस्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए धन्यवाद करता हूँ। अगली बार तक सुरक्षित रहें, आप सभी को शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

शक्तिकांत दास:

आप सभी का धन्यवाद।